

जन जन विचार

::Guwahati, Friday, 17 April 2026 :: Vol-14 Year-1 :: शुक्रवार | 17 अप्रैल 2026 | शक संवत् 1947 | वैशाख | कृष्ण | अमावस्या |:: पृष्ठ-12 | मूल्य - 5

जन चिंतन — धनेश्वर चौधरी

'तत्काल' दर्शन

पावन नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती दर्शन की नई व्यवस्था एक बड़े बदलाव का संकेत देती है। अब यहां आस्था का रास्ता सीधा मंदिर के द्वार से नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन और ऑनलाइन प्रक्रिया से होकर गुजरता है।

पहले तक 300 श्रद्धालुओं को निशुल्क ऑफलाइन पास मिलते थे। यह व्यवस्था भले ही सीमित थी, लेकिन उसमें एक मानवीय स्पर्श था—लाइन में खड़े होकर, इंतजार करके, कोई भी भक्त दर्शन का अवसर पा सकता था। अब यह रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। वही सीटें अब 200 रुपए शुल्क के साथ ऑनलाइन 'तत्काल' बुकिंग में शामिल कर दी गई हैं।

यहां सवाल केवल शुल्क का नहीं है, बल्कि उस सोच का है जिसमें भक्ति को भी एक 'सिस्टम' में ढाल दिया गया है। रेलवे की तर्ज पर 'तत्काल' शेष पृष्ठ 2 पर

बिहार के नए 'सम्राट'

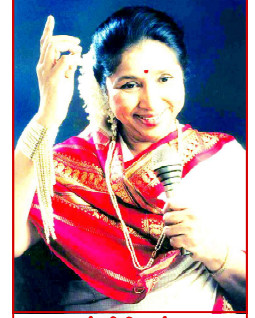


जन जन विचार ... पटना

बिहार की राजनीति में लंबे समय से चल रही अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का वह सपना

भी पूरा हो गया, जिसका इंतजार पार्टी करीब पांच दशकों से कर रही थी।

इस फैसले की जमीन काफी पहले तैयार हो चुकी थी। 30 अक्टूबर 2025 को मुंगेर के तारापुर में एक सभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से कहा था कि सम्राट जी को बड़ा नेता बनाया जाएगा। यह शेष पृष्ठ 5 पर



आशा ताई की विदाई : पृष्ठ-12

सबरीमाला पर सुप्रीम टिप्पणी

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़े बहुचर्चित मामले की सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि 'सामाजिक सुधार के नाम पर किसी धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता।'

यह मामला सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़ा है।

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटाने से सभी आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी। उस फैसले को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गईं, जिन पर अब 9 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है।

अदालत ने कहा कि धार्मिक आस्था और सामाजिक सुधार के बीच संतुलन बनाना बेहद जटिल कार्य है।

मिजोरम में शांति की नई सुबह : हमारे समझौते से खत्म हुआ तीन दशक पुराना उग्रवाद

जन जन विचार ... आइजल

पूर्वोत्तर भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में मिजोरम सरकार ने ह्यार पीपुल्स कन्वेंशन (डेमोक्रेटिक) (एचपीसी-डी) के लालहिमिंगथांगा सनाते गुट के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ ही राज्य में पिछले 33 वर्षों से जारी हमारे उग्रवाद का अंत हो गया है।

साकावर्डई में आयोजित समारोह में हुए इस समझौते को मिजोरम में स्थायी शांति की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा



रहा है। समझौते पर राज्य के गृह अध्यक्ष लालहिमिंगथांगा सनाते ने सचिव और एचपीसी-डी के हस्ताक्षर किए। शेष पृष्ठ 3 पर

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका ट्रांजिट जमानत पर रोक आना ही होगा असम

जन जन विचार ... नई दिल्ली/ गुवाहाटी

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट (अग्रिम) जमानत पर रोक लगा दी है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी पर लगाए गए कथित आरोपों से जुड़ा है।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने खेड़ा को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश असम सरकार की उस याचिका पर आया, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा दी गई राहत को चुनौती दी गई थी। शेष पृष्ठ 3 पर



क्या है पूरा मामला ?

पवन खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कथित रूप से कई पासपोर्ट होने का दावा किया था। इस बयान के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट से एक सप्ताह की ट्रांजिट बेल मिली थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

अंदर पढ़ें

3. डेकियाजुली में बंपर मतदान...
4. नीतीश होने के मायने
5. ...और बिहार में 'बड़ा भाई'...
6. तात्या टोपे : आजादी के...
7. बंगाल में बदली बयार...
9. रूस से अब और सस्ता तेल...
10. सीबीएसई 10वीं में ...
11. आर वैशाली ने रचा इतिहास

माजबाट : शंकरदेव शिशु विद्या निकेतन का शत प्रतिशत रिजल्ट

जन जन विचार ... माजबाट

असम में शिक्षा के क्षेत्र से एक सकारात्मक खबर सामने आई है। असम स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित वर्ष 2026 के एचएसएलसी परीक्षा परिणाम में माजबाट स्थित शंकरदेव शिशु विद्या निकेतन ने 100 प्रतिशत उत्तीर्ण परिणाम देकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

विद्यालय के प्रधानाचार्य रथिन दत्ता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'असम के भीतर कुछ अच्छा होता है तो बहुत खुशी होती है।'

जुबली बरुवा अव्वल



माजबाट परीक्षा केंद्र में जुबली बरुवा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए

91.83 प्रतिशत अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। उसने कुल 5511 अंक प्राप्त किए हैं। गणित में 100 अंक प्राप्त कर उन्होंने विशेष उपलब्धि हासिल की।

अनामिका रॉय की भी शानदार सफलता : इसी केंद्र की छात्रा अनामिका रॉय ने 80.16 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। उसने असमिया विषय में 100 अंक हासिल कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

माजबाट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केंद्र का कुल परिणाम 66.10 फीसदी रहा।

मंगल पांडेय की स्मृति में सिलचर में भव्य सम्मान समारोह 26 को

जन जन विचार ... सिलचर

देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक मंगल पांडेय की स्मृति में असम के सिलचर में आगामी 26 अप्रैल को एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए शहर में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में सर्वसम्मति से कार्यक्रम स्थल के रूप में विमेंस कॉलेज सिलचर का चयन किया गया।

इस समारोह में मंगल पांडेय के जीवन और उनके बलिदान पर विस्तृत चर्चा होगी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को याद किया जाएगा। बराक घाटी के विशिष्ट समाजसेवियों को सम्मानित किया जाएगा।

बैठक की अध्यक्षता पंडित रामेश्वर शास्त्री ने की। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गईं। राजन कुंवर को कार्यक्रम संयोजक,



शिवकुमार एवं प्रमोद शाह को सह-संयोजक, राहुल नुनिया को आय-व्यय निरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई।

बलिदानी मंगल पांडेय स्मृति न्यास के चेयरमैन कमलेश सिंह ने संदेश जारी कर सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सक्रिय भागीदारी निभाएं और कार्यक्रम को सफल बनाएं।

बैठक का संचालन महासचिव दिलीप कुमार ने किया। बैठक में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख हैं- रामनारायण

नुनिया, भोलानाथ यादव, सुतापा चक्रवर्ती, सीमा कुमार, द्वारका प्रसाद, जवाहरलाल पांडेय व विक्रम सिंह।

यह आयोजन न केवल महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडेय को श्रद्धांजलि देने का अवसर होगा, बल्कि नई पीढ़ी को देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देने का भी माध्यम बनेगा। सिलचर में होने वाला यह कार्यक्रम क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन के रूप में देखा जा रहा है।

साप्ताहिक राशिफल

17 से 23 अप्रैल 2026 | विक्रम संवत् 2083-मास : वैशाख, पक्ष : कृष्ण, तिथि : अमावस्या



इस सप्ताह आपके अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं रहेगी। आप अपने अधूरे कामों को पूरा करने में सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपकी पहचान मजबूत होगी।

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा। निवेश से फायदा मिल सकता है और रुके हुए पैसे वापस मिलने की संभावना है।



मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच-विचार जरूरी है।

यह सप्ताह आपके लिए भावनात्मक रूप से संतुलन लाने वाला रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और घरेलू माहौल सकारात्मक रहेगा।



सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता और सम्मान लेकर आएगा। आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और लोग आपके फैसलों को मानेंगे।

इस सप्ताह आपको छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखना होगा। ज्यादा सोचने से तनाव बढ़ सकता है।



तुला राशि वालों को इस सप्ताह संतुलन बनाए रखने की जरूरत है, खासकर आर्थिक मामलों में। खर्चों पर नियंत्रण रखें।



वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह रहस्यमय और सफलता से भरा रहेगा। आपकी योजनाएं सफल होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।



धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह यात्रा और सीख से भरा रहेगा। नई जगहों और लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा।



मकर राशि वालों को इस सप्ताह कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेगा।



कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए विचार और रचनात्मकता लेकर आएगा। आप सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे।



मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक और रचनात्मक रहेगा। कला, संगीत या लेखन से जुड़े लोगों को खास सफलता मिल सकती है।

सप्ताह के पर्व/त्योहार

- 17 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) : वरुथिनी एकादशी
- 18 अप्रैल 2026 (शनिवार) : प्रदोष व्रत (शनि प्रदोष)
- 19 अप्रैल 2026 (रविवार) : मासिक शिवरात्रि
- 22 अप्रैल 2026 (बुधवार) : अक्षय तृतीया
- 23 अप्रैल 2026 (गुरुवार) : परशुराम जयंती



● ज्योतिर्विद् आचार्य अखिलेश्वर शुक्ल
भाग्योदय : पहला तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, एमएस रोड
फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781001 मो.-94350 40387

पृष्ठ 1 का शेषांश...

‘तत्काल’ दर्शन

बुकिंग लागू करना प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन मंदिर कोई यात्रा नहीं, बल्कि आस्था का स्थल है। यहां प्रतिस्पर्धा नहीं, समानता अपेक्षित होती है।

नई व्यवस्था में सुबह 8 बजे

बुकिंग खुलेगी और कुछ ही पलों में सोंटें भर जाएंगी। ऐसे में वही लोग आगे रहेंगे जिनके पास तेज इंटरनेट, तकनीकी समझ और तुरंत भुगतान करने की क्षमता है। जो बुजुर्ग हैं, ग्रामीण हैं या डिजिटल साधनों से दूर हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया किसी परीक्षा से कम नहीं। पहले वे लाइन में लगकर भी दर्शन पा लेते थे, अब वे शायद वेबसाइट

तक ही सीमित रह जाएंगे।

यह तर्क दिया जा सकता है कि ऑनलाइन व्यवस्था से पारदर्शिता आएगी और दलाली रुकेगी। यह सही भी है, लेकिन किसी समस्या का समाधान ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरे बड़े वर्ग को ही बाहर कर दे। व्यवस्था को सरल बनाना जरूरी है, पर संवेदनशीलता के साथ।

असल प्रश्न यही है कि क्या हम सुविधा के नाम पर आस्था को कठिन बना रहे हैं? क्या यह बदलाव भक्तों को जोड़ने के बजाय उन्हें अलग नहीं कर रहा?

महाकाल के दरबार में कभी न इंटरनेट मायने रखता था, न आर्थिक स्थिति-सिर्फ श्रद्धा ही प्रवेश का आधार होती थी। अब तस्वीर बदल रही है, जहां क्लिक की गति और भुगतान

की क्षमता ही तय करेगी कि कौन दर्शन करेगा और कौन नहीं। आस्था का मार्ग अगर तकनीक और पैसे की शर्तों पर निर्भर हो जाए, तो यह सुधार नहीं, एक खामोश दूरी है- भक्त और भगवान के बीच। व्यवस्था बदलनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि व्यवस्था आगे निकल जाए और श्रद्धालु पीछे छूट जाए।

ढेकियाजुली में बंपर मतदान ने बढ़ाया सियासी रोमांच

जन जन विचार
... आनंद शर्मा,
ढेकियाजुली

असम के ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न होने के बाद सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। 9 अप्रैल को हुए मतदान में 83.29 प्रतिशत वोटिंग ने इस चुनाव को बेहद रोचक और निर्णायक बना दिया है। गांवों की चौपाल से लेकर बाजार और चाय की दुकानों तक एक ही चर्चा है- जनता ने आखिर किसे चुना? मतदान में महिलाओं की भागीदारी (83.92 प्रतिशत) पुरुषों (82.66 प्रतिशत) से अधिक रही, जिसे इस बार



चुनावी नतीजों में निर्णायक माना जा रहा है। इस सीट पर अशोक सिंहल

(भाजपा), बतास उरांग (कांग्रेस) और निर्दलीय अंशुमा बसुमतारी सहित कुल आठ

प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी उम्मीदवार अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, जिससे

मुकाबला और दिलचस्प हो गया है।

2021 में भाजपा ने इस सीट पर बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बढ़े मतदान और बदले समीकरणों के कारण मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अधिक मतदान बदलाव का संकेत हो सकता है, हालांकि इसका लाभ किसे मिलेगा, यह स्पष्ट नहीं है।

अब सबकी नजर 4 मई पर टिकी है, जब मतगणना के साथ ही सभी अटकलों पर विराम लगेगा। फिलहाल ढेकियाजुली में सियासी चर्चाएं चरम पर हैं और जनता के फैसले का इंतजार जारी है।

रोहा में अभामामस का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न



जन जन विचार
... सोयल खेतान, रोहा

रोहा स्थित श्री पंचायती ठाकुरबाड़ी प्रांगण में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन (अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन) की रोहा शाखा का सत्र 2026-28 के लिए शपथ ग्रहण समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन सिया पोद्दार ने किया, जिसमें नई कार्यकारिणी की सभी सदस्याओं ने पद एवं गोपनीयता की शपथ

ली। इस अवसर पर शाखा को पिछले कार्यकाल में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 'श्रेष्ठ नवीन शाखा' पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर की गई। नई समिति में नीतु शर्मा को अध्यक्ष, सरिता प्रजापत को उपाध्यक्ष, सुनीता शर्मा को सचिव तथा सविता अग्रवाला को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा विभिन्न प्रकल्पों के लिए भी जिम्मेदारियां तय करते हुए कुल 18 सदस्यीय टीम का गठन किया गया।

श्रीश्री दामोदरदेव की तिरोभाव तिथि 18 को

माजबाट। माजबाट क्षेत्र के बटाबारी स्थित सनातन सार्वजनिक नामघर में महापुरुष श्रीश्री दामोदरदेव की 428वीं तिरोभाव तिथि इस वर्ष भी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाएगी। आयोजन समिति द्वारा 18 अप्रैल को दिनभर विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी की गई है।

कार्यक्रम की शुरुआत सुबह धर्म ध्वजा फहराने से होगी, जिसके बाद स्मृति तर्पण, भागवत स्थापना और भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही नामघर में एक स्थायी तोरण के निर्माण हेतु आधारशिला भी रखी जाएगी। विशिष्ट पुजारी प्रदीप कुमार शर्मा के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विष्णु यज्ञ का आयोजन होगा। दोपहर में सामूहिक प्रसाद वितरण और भोग ग्रहण किया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत नलबाड़ी दुलिया भाओरिया दल द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जाएगा।

अपमानजनक टिप्पणी पर बवाल

विक्टर दास के खिलाफ सिलचर में मामला दर्ज

जन जन विचार
... सुरजीत चक्रवर्ती

सिलचर में बिष्णुप्रिया मणिपुरी समाज के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विक्टर दास के विरुद्ध सिलचर सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है। सैल्यूट तिरंगा संगठन और निखिल बिष्णुप्रिया मणिपुरी महासभा के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि विक्टर दास ने सोशल मीडिया पर मणिपुरी एवं हिंदू समुदाय के बारे में आपत्तिजनक और भ्रामक टिप्पणियां की हैं।

मीडिया से बातचीत में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे

इस प्रकार की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं और यह सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने का प्रयास है। उन्होंने यह भी बताया कि असम तथा बराक घाटी के अन्य पुलिस थानों में भी इस संबंध में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

संगठनों ने चेतावनी दी कि विक्टर दास के साथ-साथ उनके सहयोगियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। साथ ही, उन्होंने राज्य सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि उचित कदम नहीं उठाए गए, तो वे लोकतांत्रिक आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

इस अवसर पर प्रोसेनजीत देव, अनूप सिंघा, राजेश ज्ञान सहित कई लोग उपस्थित रहे।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

ट्रांजिट जमानत पर रोक...

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि पवन खेड़ा असम में नियमित अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना चाहें, तो इस आदेश से उन्हें रोक नहीं जाएगा। यानी कोर्ट ने ट्रांजिट बेल पर रोक लगाई है, लेकिन कानूनी विकल्प खुले रखे हैं।

इस फैसले को कांग्रेस के लिए एक झटका माना जा रहा है, वहीं यह मामला राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी सीमाओं के बीच संतुलन का उदाहरण भी बन गया है। आने वाले समय में खेड़ा की ओर से दिए जाने वाले जवाब और असम की

अदालतों में होने वाली सुनवाई इस केस की दिशा तय करेगी।

मिजोरम में शांति की...

हथियार छोड़ेंगे, विकास की राह पकड़ेंगे : समझौते के तहत सनाते गुट के 43 उग्रवादी हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होंगे। इसके लिए 30 अप्रैल को सेसांग में एक 'होमकमिंग समारोह' आयोजित किया जाएगा, जो हिंसा से शांति की ओर एक प्रतीकात्मक बदलाव होगा।

विकास बनेगा शांति का आधार

यह समझौता केवल उग्रवाद समाप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमार बहुल सिनलुंग हिल्स क्षेत्र के समग्र विकास पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत-विशेष विकास पैकेज और बढ़ा हुआ बजट, सड़क, कनेक्टिविटी

और बुनियादी ढांचे का विस्तार, शिक्षा संस्थानों और आवासीय सुविधाओं की स्थापना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार को शामिल किया गया है।

सरकार ने भरोसा दिलाया है कि एचपीसी-डी की मांगों को प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा।

सांस्कृतिक पहचान को भी मिला सम्मान : समझौते में हमार समुदाय के सबसे बड़े त्योहार सिकपुइ रई को आधिकारिक मान्यता देने का भी प्रावधान है। साथ ही 'हमार शहीद दिवस' को स्थानीय अवकाश घोषित करने की मांग पर भी सकारात्मक रुख दिखाया गया है।

तीन समझौतों के बाद पूर्ण शांति

मिजोरम सरकार ने इससे पहले 1994

और 2018 में भी हमार संगठनों के साथ समझौते किए थे। ताजा समझौता अंतिम सक्रिय गुट के साथ होने के कारण अब राज्य में उग्रवाद का पूर्ण अंत माना जा रहा है।

नई शुरुआत की उम्मीद

मुख्यमंत्री के सलाहकारों और अधिकारियों ने इसे 'मिल का पत्थर' बताते हुए कहा कि उग्रवाद अक्सर विकास की कमी से जन्म लेता है। इस समझौते के साथ अब मिजोरम में विकास और शांति साथ-साथ आगे बढ़ेंगे। हमार नेतृत्व ने भी स्वीकार किया कि भले ही सभी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन यह समझौता आपसी विश्वास और स्थायी समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

संपादकीय

बिहार में 'बड़े भाई' की राजनीति

बिहार की राजनीति में हालिया बदलाव महज नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि गठबंधन राजनीति के नए स्वरूप का संकेत है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सहयोगी दल की भूमिका से आगे बढ़कर निर्णायक शक्ति बन चुकी है। वर्षों तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजनीति करने वाली भाजपा ने अब सत्ता का केंद्र अपने हाथ में ले लिया है।

यह घटनाक्रम महाराष्ट्र के राजनीतिक मॉडल से मेल खाता है, जहां देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा ने गठबंधन को बनाए रखते हुए धीरे-धीरे नियंत्रण हासिल किया। बिहार में भी यही रणनीति अपनाई गई—पहले सीटों में बढ़त, फिर महत्वपूर्ण विभागों पर पकड़ और अंततः नेतृत्व परिवर्तन।

हालांकि, यह रणनीति राजनीतिक दृष्टि से प्रभावी जरूर है, लेकिन इसके दूरगामी प्रभावों पर सवाल उठते हैं। क्या यह गठबंधन धर्म का सम्मान है या सहयोगियों को कमजोर कर वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया? लोकतंत्र में गठबंधन बराबरी और विश्वास पर आधारित होते हैं, न कि शक्ति संतुलन के खेल पर।

बिहार का यह प्रयोग भविष्य की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। यदि सहयोगी दलों में असंतोष बढ़ता है, तो यह मॉडल अस्थिरता भी पैदा कर सकता है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति में अब गठबंधन नहीं, बल्कि प्रभाव और नियंत्रण की राजनीति हावी होती जा रही है।

सुलगाता सवाल आपके विचार

सरकारी जमीन हथियाने की साजिश

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हालिया बवाल ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे समाज में प्रतीकों का इस्तेमाल अब सियासी और निजी स्वार्थों के लिए किया जाने लगा है? पहली नजर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से जुड़ा विवाद भावनात्मक प्रतीक होता है, लेकिन जांच में सामने आया कि इसके पीछे असल खेल सरकारी जमीन पर कब्जे का था।

यह घटना केवल कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता का भी परिणाम है। वर्षों से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे होते रहे और जिम्मेदार तंत्र मौन बना रहा। नतीजा यह हुआ कि एक सुनियोजित साजिश ने सामाजिक तनाव का रूप ले लिया। पंचायत चुनाव के माहौल में इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश ने आग में घी का काम किया।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि बाहरी शरारती तत्वों द्वारा पत्थरबाजी और हिंसा ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे मामलों में असाामाजिक ताकतों के का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं।

अब जब प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है, तो सवाल यह है कि क्या यह कदम पहले नहीं उठाए जा सकते थे?

लखीमपुर की घटना चेतना की है कि यदि शासन समय रहते सतर्क न हो, तो छोटे विवाद भी बड़े सामाजिक संकट में बदल सकते हैं। जरूरत है सख्त प्रशासन, पारदर्शिता और ऐसी राजनीति से दूरी की, जो समाज को बांटकर लाभ उठाती है।

नीतीश होने के मायने

जन जन विचार
... प्रणय विक्रम सिंह

आज बिहार की राजनीति के आंगन में एक अजीब सी नमी उतर आई है। जैसे किसी घर से बेटी विदा हो रही हो। आंगन वही है, दीवारें वही हैं, दरवाजा भी खुला है, पर भीतर एक सूनापन धीरे-धीरे फैलता जा रहा है। मां की आंखें भरी हैं, भाई की आवाज अटक गई है और घर का हर कोना मानो स्मृतियों में सिमट गया है।

मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार का इस्तीफा भी कुछ ऐसा ही है। यह सत्ता का परिवर्तन नहीं, एक संवेदना का संधि-विराम है। एक ऐसे युग का अवसान, जिसने बिहार को अंधकार से आलोक, अव्यवस्था से अनुशासन और भय से विश्वास तक पहुंचाया।

एक समय था जब बिहार का नाम सुनते ही मन में भय की परछाईयां उतर आती थीं। 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में यह राज्य अपहरण, अपराध और अराजकता की त्रासदी से जूझ रहा था। अपहरण उद्योग



एक कड़वी सच्चाई बन चुका था, कानून-व्यवस्था चरमराई हुई थी, और जातीय संघर्षों की आग गांव-गांव तक फैली हुई थी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शासन की उपस्थिति वैसी ही थी, जैसे किसी सूखे खेत में बादलों की परछाई दिखती तो है, पर बरसती नहीं।

ऐसे समय में नीतीश कुमार आए। न घोषणाओं के शोर के साथ, न सत्ता के अहंकार के साथ, बल्कि एक शांत संकल्प के साथ। जैसे कोई बड़ा भाई टूटते घर की दीवारों को चुपचाप सहारा देता है। उन्होंने सबसे पहले उस भय को तोड़ा, जिसने बिहार की आत्मा को जकड़ रखा था। तेज दायल की व्यवस्था, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और प्रशासनिक जवाबदेही, इन सबने मिलकर एक नया संदेश दिया कि अब कानून केवल कितानों में नहीं, जमीन पर भी दिखेगा। आंकड़े बताते हैं कि उनके शुरुआती कार्यकाल में ही लगभग 1.5 लाख से अधिक अपराधिक मामलों का त्वरित निपटारा हुआ और 50,000 से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई गई। अपहरण जैसे संगठित अपराधों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई। यह केवल आंकड़े नहीं थे, यह उस मां की आंखों में लौटता हुआ विश्वास था, जो शाम ढलने पर अपने बेटे के सुरक्षित लौटने की दुआ करती थी।

जातीय संघर्षों की आग, जिसने बिहार को लंबे समय तक झुलसाया, वह भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। नरसंहारों की स्मृतियां अभी जीवित थीं। समाज टुकड़ों में बंटा हुआ था। ऐसे में उन्होंने टकराव नहीं, तटस्थता और समरसता का सेतु बनाया। 'विकास के साथ न्याय' का उनका मंत्र किसी राजनीतिक भाषण का हिस्सा नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन का सूत्र बन गया। उन्होंने महादलित आयोग का गठन किया, अति पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं चलाई, मानो हर उस छूटे हुए हाथ को थाम लिया हो, जो वर्षों से व्यवस्था से दूर था।

नक्सलवाद, वह जख्म जो बिहार के कई जिलों में गहराई तक धंसा हुआ था। वहां उन्होंने केवल सुरक्षा बलों की शक्ति नहीं, विकास की भाषा को भी उतारा। आंकड़े बताते हैं कि उनके कार्यकाल में ग्रामीण सड़कों का जाल 60,000 किलोमीटर से अधिक तक विस्तारित हुआ। यह सड़कें केवल कन्नौट की पट्टियां नहीं थीं, ये वे धमनियां थीं, जिनसे विकास का रक्त गांवों तक पहुंचा। जहां पहले भय

था, वहां अब बसें चलने लगीं, जहां पहले बंदूक की गूंज थी, वहां अब बच्चों की किलकारियां सुनाई देने लगीं।

शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान किसी क्रांति से कम नहीं रहा। 'मुख्यमंत्री साइकिल योजना' के अंतर्गत करीब 2 करोड़ से अधिक साइकिलें छात्र-छात्राओं को वितरित की गईं। यह साइकिल केवल एक साधन नहीं थी। यह उस बेटे के सपनों का पहिया थी, जो पहली बार स्कूल की चौखट

पार कर रही थी। 'पोशाक योजना' और छात्रवृत्तियों ने शिक्षा को सम्मान से जोड़ा। स्कूलों में नामांकन बढ़ा, डॉपआउट दर घटी, यह सब मिलकर उस समाज का निर्माण कर रहे थे, जहां शिक्षा अब विशेषाधिकार नहीं, अधिकार बनने लगी।

महिलाओं के सशक्तिकरण में उनका निर्णय ऐतिहासिक रहा। पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण का ही सुफल है कि आज बिहार में 15 लाख से अधिक महिला जनप्रतिनिधि सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह केवल प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि समाज के स्वरूप का पुनर्निर्माण है कि जैसे किसी घर की चौखट, जो अब भीतर-बाहर दोनों को बराबर

जोड़ती है।

स्वास्थ्य सेवाओं में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या, जो पहले लाखों में सीमित थी, बढ़कर करोड़ों तक पहुंची, यह केवल संख्या का विस्तार नहीं, बल्कि विश्वास की वापसी थी।

शराबबंदी का निर्णय किसी नीति से अधिक एक पीड़ा की प्रतिक्रिया था। 2016 में लागू इस कानून ने समाज में व्यापक बहस को जन्म दिया। इसके प्रभावों पर मतभेद हो सकते हैं, पर इसकी भावना स्पष्ट थी, उस परिवार को बचाना, जो नशे की लत में टूट रहा था। यह उस मां की आंखों से आंसू पोंछने का प्रयास था, जो अपने घर को बिखरते देख रही थी।

आर्थिक दृष्टि से बिहार ने एक नई गति पकड़ी। कई वर्षों तक राज्य की विकास दर 10 प्रतिशत से अधिक रही, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं आगे थी। बिजली, सड़क, शिक्षा हर क्षेत्र में सुधार ने बिहार को पिछड़ेपन के प्रतीक से संभावनाओं के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया।

हां, इस यात्रा में विरोधाभास भी थे। गठबंधनों का बदलना, राजनीतिक समीकरणों का लचीलापन, इन सबने उन्हें आलोचना का विषय भी बनाया। परंतु यही राजनीति का वह यथार्थ है, जहां सिद्धांत और परिस्थितियों के बीच संतुलन साधना पड़ता है। नीतीश कुमार उसी संतुलन के साधक रहे। न पूरी तरह आदर्शवादी, न पूरी तरह व्यवहारवादी, बल्कि दोनों के बीच एक सेतु।

आज जब वे जा रहे हैं, तो यह वैसा ही क्षण है जैसे बेटे की विदाई। सब कुछ व्यवस्थित है, पर मन अस्त-व्यस्त है। घर खड़ा है, पर आंगन सूना है। उनके जाने के साथ केवल एक पद नहीं खाली हुआ— एक शैली, एक संस्कार, एक संतुलन भी जैसे विदा हो रहा है। यह विदाई केवल एक व्यक्ति की नहीं, एक विश्वास, एक व्यवस्था और एक पूरे युग की है।

'नीतीश कुमार होने के मायने' शायद यही हैं कि आप अराजकता में अनुशासन की अल्पना रचें, अंधकार में आशा का दीप जलाएं और बिखरते समाज को फिर से जोड़ने का धैर्य रखें।

वे गए नहीं हैं, वे बस इतिहास में दर्ज हो गए हैं, जहां नाम नहीं, निशान बोलते हैं।

...और बिहार में 'बड़ा भाई' बन गईं भाजपा

मुख्यमंत्री ने गृह समेत रखे 29 विभाग, जदयू के खात में आए केवल 18 विभाग

जन जन विचार

...क पटना

भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनते ही विभागों के प्रारंभिक बंटवारे की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह, सामान्य प्रशासन, नगर विकास, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पथ निर्माण समेत कुल 29 विभाग अपने पास रखे, जबकि दोनों उप मुख्यमंत्री को मिलाकर जनता दल यूनाइटेड को मात्र 18 विभाग दिए गए।

गृह विभाग सहित मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भू-तत्व, नगर विकास एवं आवास,



स्वास्थ्य, विधि, उद्योग, पथ निर्माण, कृषि, लघु जल संसाधन, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा रोजगार एवं कौशल विकास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण,

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल, सहकारिता, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, गन्ना उद्योग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण एवं पंचायती राज विभाग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फिलहाल अपने पास रखे हैं।

जनता दल यूनाइटेड के खाते में फिलहाल 18 विभाग ही आए हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जन-संपर्क, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, परिवहन और उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को ग्रामीण विकास, परिवहन, उच्च शिक्षा, ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, वित्त, वाणिज्य-कर, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण और ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

बिहार : मंच पर नई सरकार, कोने में पुराना मुखिया

जन जन विचार

...क पटना

भारतीय राजनीति में सत्ता का हस्तांतरण अक्सर संघर्ष, समीकरण और महत्वाकांक्षाओं के बीच होता है। लेकिन, कभी-कभी इतिहास ऐसे पल भी दर्ज करता है, जब सत्ता से मोहभंग नहीं, बल्कि एक सधी हुई दूरी दिखाई देती है।

बिहार में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम कुछ ऐसा ही दृश्य लेकर आया, जब राज्य के मुखिया रहे नीतीश कुमार ने दो दशकों तक राज्य का नेतृत्व करने के बाद बेहद शांत और संयमित तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कर दिया।

करीब 21 वर्षों तक बिहार की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे के केंद्र में रहे नीतीश कुमार राज्य को विकास, सुशासन और बुनियादी



ढांचे के नए आयाम देते रहे। उनके कार्यकाल में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलावों की चर्चा होती रही। ऐसे नेता का सत्ता से हटना सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम नहीं।

एक कोने में शांत बैठे दिखे नीतीश

राजभवन परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दृश्य कुछ अलग ही था। मंच पर नई सरकार के चेहरे थे, लेकिन एक कोने में बैठे नीतीश कुमार का शांत

और स्थिर चेहरा पूरे राजनीतिक परिदृश्य को एक अलग अर्थ दे रहा था। न उनके साथ मंत्रियों का काफिला था, न ही प्रशासनिक अधिकारियों की भीड़।

नीतीश वही नेता थे, जिनके इर्द-गिर्द वर्षों तक सत्ता का केंद्र घूमता रहा। शपथ ग्रहण के बाद उनका अपने सरकारी वाहन के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा करना भी एक प्रतीकात्मक दृश्य बन गया। राजनीतिक विश्लेषक इसे सत्ता से उनके सहज अलगाव के रूप में देख रहे हैं। न कोई सार्वजनिक असंतोष, न कोई कटाक्ष, सिर्फ एक मौन स्वीकृति।

इस घटना को कई नजरियों से देखा जा रहा

राजनीतिक हलकों में इस घटना को कई नजरियों से देखा जा रहा है। एक पक्ष इसे गठबंधन राजनीति

की मजबूरी मान रहा है, तो दूसरा इसे व्यक्तिगत शौली और राजनीतिक संस्कार का उदाहरण बता रहा है। दरअसल, भारतीय राजनीति में जहां पद और प्रभाव को बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाते हैं, वहां इस तरह का शांत हस्तांतरण दुर्लभ माना जाता है।

नीतीश कुमार की छवि हमेशा एक संयमित और कार्य-केंद्रित नेता की रही है। उन्होंने कई बार सत्ता परिवर्तन के दौर देखे, लेकिन इस बार का दृश्य अलग था। यह सत्ता से विदाई का नहीं, बल्कि एक सधे हुए विराम का संकेत था।

बिहार की राजनीति अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन पीछे छोटे इस दृश्य ने यह जरूर याद दिलाया है कि सत्ता का असली अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि उसे छोड़ने की क्षमता भी है।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

बिहार के नए 'सम्राट'

बयान उस समय महज राजनीतिक संदेश लगा, लेकिन अब वह भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है।

इसके बाद हाल ही में 'समृद्धि यात्रा' के दौरान नीतीश कुमार ने भी कई बार संकेत दिए कि उनके बाद जिम्मेदारी सम्राट चौधरी संभाल सकते हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर सम्राट के कंधे पर हाथ रखकर यह संदेश और स्पष्ट कर दिया।

हालांकि, अंतिम फैसले से पहले स्थिति पूरी तरह साफ नहीं थी। कई नाम चर्चा में थे और यह

भी माना जा रहा था कि भाजपा किसी नए चेहरे से चौंका सकती है। लेकिन अंततः पार्टी ने उसी नाम पर मुहर लगाई, जो सबसे ज्यादा चर्चा में था और जो सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) और नीतीश कुमार-दोनों के लिए स्वीकार्य था।

14 अप्रैल को सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया और इसी के साथ उनका मुख्यमंत्री बनना तय हो गया। अगले दिन 15 अप्रैल को उन्होंने शपथ ली। दिलचस्प बात यह रही कि जिस दिन नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, उस दिन भी सम्राट उनके साथ ही नजर आए, जिससे सत्ता हस्तांतरण की सहजता साफ दिखी।

मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट

चौधरी ने अपने संबोधन में शीर्ष नेतृत्व और सहयोगियों का आभार जताया। उन्होंने खास तौर पर नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने शासन चलाने का तरीका सिखाया है और बिहार के विकास के लिए सभी मिलकर काम करेंगे।

सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर भी उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने अपने पिता शकुनी चौधरी के साथ राजनीति की शुरुआत की, फिर राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े और राबड़ी देवी सरकार में मंत्री बने। बाद में जीवन राम मांझी के साथ भी रहे और आखिरकार 2018 में भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में आने के बाद उनका कद लगातार बढ़ता गया।

वे उन चुनिंदा नेताओं में हैं,

जिन्होंने राबड़ी देवी, जीवन राम मांझी और नीतीश कुमार-तीनों सरकारों में मंत्री के रूप में काम किया और कई अहम विभाग संभाले। यही अनुभव उन्हें मजबूत दावेदार बनाता है।

हालांकि उनके नाम पर शुरुआत में पूरी सहमति नहीं थी। कुछ वर्ग उन्हें पार्टी का 'आउटसाइडर' भी मानते थे और आरएसएस के भीतर भी अलग राय बताई जाती रही। लेकिन अंततः नीतीश कुमार का भरोसा उनके पक्ष में निर्णायक साबित हुआ।

सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी यह फैसला अहम है। सम्राट चौधरी कुशावाहा समुदाय से आते हैं, जो राज्य में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है।

ऐसे में यह बदलाव बिहार की राजनीति में नए सामाजिक संतुलन का संकेत भी देता है—जहां सत्ता अब नीतीश के कुर्मी नेतृत्व से आगे बढ़कर कुशावाहा नेतृत्व की ओर जाती दिख रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि भाजपा की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है—जिसका मकसद बिहार में अपनी स्वतंत्र और मजबूत पकड़ बनाना है।

फिलहाल, सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को साबित करने की होगी—क्या वे नीतीश कुमार जैसी लंबी और प्रभावशाली पारी खेल पाएंगे, यह आने वाला समय तय करेगा।

विचार

लक्ष्य तय करो और उसे पाने की कोशिश करो।

लघु कथा

लगन का जादू

एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास पढ़ने के लिए न तो अच्छे साधन थे और न ही बिजली की सुविधा। फिर भी वह हर दिन एक दीये की रोशनी में पढ़ाई करता था।

गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, 'इतनी मेहनत से क्या होगा?' लेकिन राहुल ने कभी हार नहीं मानी। वह रोज मेहनत करता और अपने सपनों को याद रखता।

एक दिन परीक्षा का परिणाम आया। राहुल पूरे स्कूल में प्रथम आया। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे।

राहुल ने साबित कर दिया कि सफलता साधनों से नहीं, मेहनत और लगन से मिलती है।

पहेलियां

1. कौन-सी चीज है, जिसे आप खाते भी हैं और पहनते भी हैं?
2. ऐसी कौन-सी चीज है, जो टूटती है लेकिन आवाज नहीं करती?
3. एक घर में दो भाई रहते हैं, दोनों साथ-साथ चलते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं।
4. ऐसी कौन-सी चीज है, जो खुद चलती नहीं, फिर भी पूरी दुनिया घूमती है?
5. मैं काला हूँ, पर रोशनी देता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ?

उत्तर : लौंग, नींद, जूते, सूरज, कोयला/ब्लैकबोर्ड।

जरा हंस लो

टीचर : अगर मैं तुम्हें दो आम दूँ और दो आम और दूँ तो कितने आम होंगे?

गोलू : पांच!

टीचर : कैसे?

गोलू : मेरे पास पहले से एक आम है।

तात्या टोपे : आजादी के सच्चे योद्धा

तात्या टोपे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। उनका जन्म 1814 में महाराष्ट्र के येवला में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत बहादुर और बुद्धिमान थे।

तात्या टोपे के सबसे अच्छे मित्र नाना साहेब थे। जब 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, तब तात्या टोपे ने सेनापति बनकर अंग्रेजों से मुकाबला किया।

उन्होंने अपनी गुरिल्ला युद्ध शैली (छापामार युद्ध) से अंग्रेजों को बहुत परेशान किया। वे जंगलों और अलग-अलग जगहों पर अचानक हमला करते थे और फिर गायब हो जाते थे। इससे अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाते थे।

तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद की और कई लड़ाइयों में बहादुरी से लड़े। अंत में विश्वासघात के कारण वे पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फासी दे दी गई।

तात्या टोपे को 'महाराष्ट्र का बाघ' कहा जाता है। उनकी वीरता और देशभक्ति हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने देश से प्रेम करना चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़े रहना चाहिए।



1857 का विद्रोह और तात्या टोपे की भूमिका

कानपुर में विद्रोह भड़काने पर नाना साहेब को पेशवा घोषित किया गया और तात्या टोपे सेनापति नियुक्त किया गया। उन्होंने कानपुर की रक्षा की, झांसी और कालपी की लड़ाइयों में रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की, तथा ग्वालियर पर अधिकार किया। ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज और कार्लिन कैम्पबेल जैसे सेनाओं के सामने बार-बार नई रणनीति अपनाकर वे एक वर्ष तक सक्रिय रहे।

गुरिल्ला युद्ध और अंतिम संघर्ष

ग्वालियर की पराजय के बाद तात्या टोपे ने मध्य भारत, राजस्थान और गुजरात के अरण्यों में छापामार युद्ध जारी रखा। उन्हें पकड़ना अंग्रेजों के लिए कठिन सिद्ध हुआ। अंततः नरवर के राजा मानसिंह के विश्वासघात से वे 8 अप्रैल 1859 को पकड़े गए, 15 अप्रैल को कोर्ट-मार्शल हुआ और 18 अप्रैल को शिवपुरी में फांसी दी गई। हालांकि, कुछ इतिहासकारों के अनुसार वे युद्ध में ही शहीद हुए या बाद में गुजरात में गुमनाम जीवन जिए।

विरासत और स्मारक

तात्या टोपे को 'महाराष्ट्र का बाघ' कहा जाता है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया और शिवपुरी में तात्या टोपे स्मारक स्थल निर्मित किया। 1857 की क्रांति के जब भी उल्लेख होते हैं, तात्या टोपे के साहस और बलिदान को अमर नायक के रूप में स्मरण किया जाता है।

विश्व पुस्तक दिवस



हर वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। यह दिन पुस्तकों के महत्व, पढ़ने की आदत और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

शुरुआत कैसे हुई?

इस दिवस की शुरुआत यूनेस्को ने 1995 में की। 23 अप्रैल को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर और मिगेल दे सर्वान्तेस का निधन हुआ था।

उद्देश्य

लोगों में पढ़ने की आदत विकसित करना

ज्ञान और शिक्षा का प्रसार लेखकों, प्रकाशकों और कॉपीराइट का सम्मान

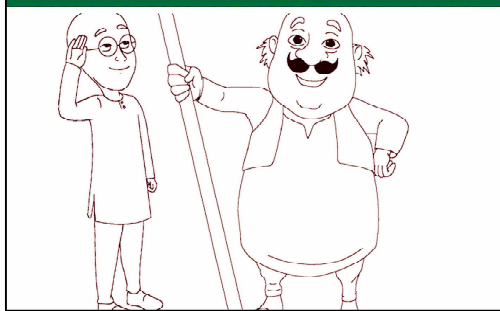
महत्व

पुस्तकें हमारे जीवन की सच्ची मित्र होती हैं। वे न केवल ज्ञान देती हैं बल्कि सोचने, समझने और व्यक्तित्व विकास में भी मदद करती हैं। डिजिटल युग में भी किताबों का महत्व कम नहीं हुआ है।

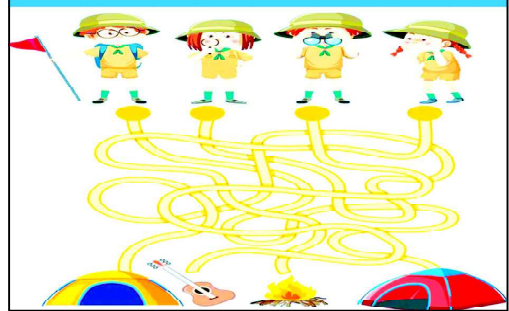
कैसे मनाएं?

पुस्तक पढ़ने की आदत शुरू करें। बच्चों को कहानी की किताबें पढ़ाएं। पुस्तकालय जाएं या नई किताब खरीदें। दोस्तों को किताब गिफ्ट करें।

रंग भरो



रास्ता ढूंढो



बंगाल में बदली बयार, तमिलनाडु में परंपरागत राजनीति की कसौटी



देश की राजनीति इन दिनों दो बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी माहौल के इर्द-गिर्द घूम रही है।

बंगाल : क्या बदल रही है राजनीतिक धुरी ?

पश्चिम बंगाल की राजनीति इस बार दिलचस्प मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। लंबे समय से सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस के सामने इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सीधे चुनौती पेश की है। ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता और जनाधार पर सवाल खड़े करने की कोशिशें तेज हुई हैं।

इस चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव भाजपा की रणनीति में देखने को मिल रहा है। पहले जहां पार्टी मुख्य रूप से बड़े-बड़े बयान और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप पर निर्भर रहती थी, वहीं इस बार वह जमीनी स्तर पर जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाने में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में उमड़ती भीड़ को भाजपा अपने पक्ष में बनते माहौल का संकेत मान रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी के हालिया बयानों में जो तीखापन और आक्रामकता दिख रही है, वह कहीं न कहीं बढ़ते दबाव की ओर इशारा करती है। करीब डेढ़ दशक से सत्ता में रहने के कारण तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक

स्वाभाविक एंटी-इन्कम्बेंसी भी उभर रही है, जिसे भाजपा भुनाने की कोशिश कर रही है।

‘मोदी बनाम ममता’ नहीं, ‘विजन बनाम व्यवस्था’ की रणनीति

इस बार भाजपा की रणनीति का एक और अहम पहलू यह है कि वह चुनाव को पूरी तरह से ‘मोदी बनाम ममता’ की लड़ाई में नहीं बदलना चाहती। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व राज्य के विकास, सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों के विजन पर जोर दे रहा है, जबकि स्थानीय नेता ही ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब दे रहे हैं।

यह रणनीति बंगाल की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई प्रतीत होती है, जहां स्थानीय पहचान और भाषा का विशेष महत्व है। भाजपा इस बार मतदाताओं को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि वे बिना किसी भय के मतदान करें और बदलाव का हिस्सा बनें।

तमिलनाडु : क्षेत्रीय दलों के वर्चस्व की परीक्षा

जहां बंगाल में मुकाबला तेज और बहुआयामी होता जा रहा है, वहीं तमिलनाडु में राजनीति अभी भी परंपरागत ढांचे के भीतर सिमटी हुई नजर आती है। यहां मुख्य मुकाबला द्रविड़ मुनेत्र कषमग और

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषमग के बीच ही केंद्रित है।

एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके लगातार सत्ता में बनी हुई है। हालांकि लंबे समय तक शासन करने के कारण उसके खिलाफ भी कुछ असंतोष पनपने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वह बिंदु है, जिस पर एआईएडीएमके अपनी उम्मीदें टिका रही है।

लेकिन एआईएडीएमके के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेतृत्व की है। पार्टी में फिलहाल कोई ऐसा चेहरा नहीं उभर पाया है, जो व्यापक जनसमर्थन जुटा सके। इससे उसकी चुनावी मजबूती पर प्रश्नचिह्न लगते हैं।

भाजपा की सीमित भूमिका, लेकिन रणनीतिक उपस्थिति

तमिलनाडु में भाजपा की स्थिति बंगाल की तुलना में काफी अलग है। यहां वह सीमित सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषमग के साथ गठबंधन में है। ऐसे में भाजपा के लिए अपने दम पर बड़ा राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना आसान नहीं है। फिर भी, भाजपा राज्य में अपनी उपस्थिति को धीरे-धीरे मजबूत करने की रणनीति पर काम कर



रही है। यह उसके दीर्घकालिक विस्तार की योजना का हिस्सा माना जा सकता है।

बंगाल चुनाव : कई सीटों पर निर्णायक साबित हो सकते हैं हिंदीभाषी वोटर

बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार हिंदी भाषी मतदाताओं की भी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य के शहरी और औद्योगिक इलाकों में हिंदीभाषी आबादी का प्रभाव लगातार बढ़ा है, जिसका सीधा असर चुनावी गणित पर पड़ सकता है।

राजनीतिक दल खासकर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा इस वोट बैंक को साधने के लिए अलग-अलग रणनीतियों पर काम कर रहे हैं।

हिंदीभाषी मतदाता को लुभाने की कोशिश

राज्य की कुल आबादी 10.50 करोड़ के आसपास है। इनमें अनुमानित हिंदी भाषी आबादी लगभग 1.40 करोड़ है, जबकि एक करोड़ के आसपास मतदाता हैं। हिंदीभाषी वोटर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं।

कोलकाता के बड़ाबाजार, बेहाला, दमदम के अलावा आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, खड़गपुर, सिलीगुड़ी, मालदा, हावड़ा और हुगली के औद्योगिक क्षेत्र, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के शहरी क्षेत्र और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में हिंदी भाषियों की अच्छी-खासी तादाद है।

इन क्षेत्रों में करीब 50 से 55 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां हिंदी भाषी वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। हिंदी भाषी वोटर अक्सर एकजुट होकर मतदान करते हैं, जिससे उनका प्रभाव और बढ़ जाता है।

शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में है पकड़ : हिंदी भाषी मतदाताओं पर टीएमसी व भाजपा दोनों की नजर है। भाजपा पहले से ही इस वर्ग में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में रही है।

हिंदी भाषी उम्मीदवारों को टिकट देना और हिंदी में प्रचार अभियान चलाना इसकी रणनीति का अहम हिस्सा है।

भाजपा ने हिंदी भाषी व्यापारियों को साधने की कोशिश की है। पूर्व सांसद व भाजपा नेता अर्जुन सिंह का मानना है कि हिंदी भाषी मतदाता उसके पारंपरिक समर्थन आधार का हिस्सा बन सकते हैं, खासकर शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में।

दूसरी तरफ टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी हिंदी भाषियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए पहल की है। ममता सरकार ने राज्य के पहले हिंदी विश्वविद्यालय के साथ हिंदी अकादमी की स्थापना की है। छठ पर्व पर दो दिन की सरकारी छुट्टी की भी घोषणा की है।

हिंदी अकादमी के सदस्य तथा वरिष्ठ टीएमसी नेता अशोक झा का कहना है कि पार्टी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह केवल बंगाली नहीं बल्कि हिंदीभाषियों की भी प्रतिनिधि है।

भाजपा-टीएमसी दोनों ने दिए हिंदी भाषियों को टिकट

भाजपा व टीएमसी दोनों ने इस बार चुनाव में कई हिंदी भाषी उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। भाजपा के प्रमुख हिंदी भाषी उम्मीदवारों में नोआपाड़ा से अर्जुन सिंह, भाटपाड़ा से उनके पुत्र पवन सिंह, चौरंगी से संतोष पाठक, कोलकाता पोर्ट से राकेश सिंह, उत्तर हावड़ा से उमेश राय, काशीपुर बेलगछिया से रितेश तिवारी, पांडेश्वर जितेंद्र तिवारी शामिल हैं।

तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख हिंदी भाषी उम्मीदवारों में बाली से कैलाश मिश्रा, जमुड़िया से हरेराम सिंह, बाराबनौरी से विधान उपाध्याय व जोड़ासांको से विजय उपाध्याय व अन्य शामिल हैं।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

सबरीमाला पर सुप्रीम टिप्पणी

न्यायमूर्तियों ने माना कि लाखों लोगों की मान्यताओं को गलत ठहराना आसान नहीं है।

जस्टिस बीवी नागरला ने कहा, ‘हम सामाजिक सुधार के नाम पर किसी धर्म को खोखला नहीं कर सकते।’ सुनवाई के दौरान संविधान के तीन

अहम प्रावधान चर्चा में रहे-

अनुच्छेद 25 : हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 26 : धार्मिक संस्थाओं को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार

अनुच्छेद 25(2) (डू) : सरकार को सामाजिक सुधार के लिए हस्तक्षेप का अधिकार

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि, अदालत को यह तय नहीं

करना चाहिए कि कौन-सी प्रथा ‘आवश्यक’ है। धार्मिक परंपराओं का मूल्यांकन समुदाय के दृष्टिकोण से होना चाहिए, न कि बाहरी मानकों से।

इस केस में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है- क्या अदालत यह तय कर सकती है कि कोई धार्मिक प्रथा ‘आवश्यक’ है या नहीं? कुछ न्यायाधीशों ने इस सिद्धांत पर पुनर्विचार की आवश्यकता जताई।

साथ ही यह भी पूछा गया कि क्या

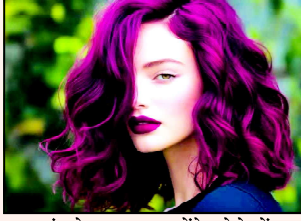
बिना संबंधित समुदाय की व्यापक सुनवाई के ऐसा फैसला संभव है ?

पृष्ठभूमि : आस्था बनाम समानता सबरीमाला मंदिर में भगवान अय्यप्पा को ब्रह्मचारी माना जाता है। इसी आधार पर परंपरागत रूप से कुछ आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर रोक रही है।

2018 के फैसले में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने कहा था कि ‘भक्ति में भेदभाव नहीं हो सकता।’

बिना केमिकल बालों को रंगें बरगंडी

आज के समय में ज्यादातर लोग बालों को कलर करना पसंद कर रहे हैं। बरगंडी शेड को लोगों को काफी पसंद आ रहा है। हालांकि, बाजार में मिलने वाले हेयर डाय में केमिकल होते हैं, जो लंबे समय में बालों को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे में हम आपको बालों को नेचुरली कलर करने का आसान तरीका बता रहे हैं।



आज के समय में हर कोई अपने बालों का बहुत ख्याल रखता है। कोई पार्लर जाकर महंगे हेयर स्पा करवाता है, तो कुछ लोगों को हेयर कलर करवाने का शौक होता है। हालांकि, इन सबके लिए आपको अच्छी खासी अमाउंट भी पे करना होता है, लेकिन आप चाहें तो बालों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे भी आजमा सकती हैं। इससे आपके बाल न केवल शाइनी बनेंगे बल्कि उन्हें मजबूती भी मिलेगी।

हेयर कलर की बात करें तो बाजारों में कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इनमें केमिकल भी होते हैं, जिससे बालों को काफी नुकसान भी पहुंचता है। ऐसे में अगर आपको बालों में बरगंडी रंग चाहिए, तो हम आपको एक आसान सा घरेलू नुस्खा बता रहे हैं। इससे आपके बाल नेचुरली बरगंडी रंग में हो जाएंगे। आइए जानते हैं-

कैसे करें बालों को रंग ?

अगर आप बालों को नेचुरली कलर करना चाहती हैं तो इसके लिए गुड़हल के फूल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे बालों को लाइट बरगंडी टोन मिलता है और साथ ही इसके इस्तेमाल से बाल हेल्दी भी रहते हैं। अगर आप भी बिना केमिकल के बालों को कलर करना चाहती हैं, तो ये तरीका आपके बहुत काम आ सकता है।

गुड़हल के फूल से हेयर डाय बनाने के लिए क्या चाहिए ?

5 से 6 गुड़हल के फूल, 2 चम्मच आंवला का पाउडर, 1 चम्मच मेहंदी (ऑप्शनल), पानी (जरूरत के अनुसार)

कैसे बनाएं ?

इसे बनाने के लिए गुड़हल के फूलों को धोकर पीस लें अब इसमें आंवले का पाउडर मिलाएं अगर आप डार्क कलर चाहती हैं, तो थोड़ा मेहंदी भी डाल सकती हैं जरूरत के हिसाब से पानी डालकर पेस्ट बना लें आपका नेचुरल हेयर डाय तैयार है

कैसे करें इस्तेमाल ?

इस पेस्ट को बालों और स्कैल्प पर अच्छे से लगा लें इसे कम से कम 45 मिनट तक लगा रहने दें फिर बालों को धो लें

ध्यान रहे कि इस्तेमाल करने से पहले ही आपको बालों में शैंपू कर लेना है, क्योंकि साफ बालों में ही कलर चढ़ता है। वहीं डाय लगाने के बाद बालों में शैंपू न लगाएं।

क्या रिजल्ट मिलेगा ?

एक बार में बहुत डार्क बरगंडी कलर नहीं मिलेगा। अगर आप इसे दो से तीन बार इस्तेमाल करती हैं तो जरूर फर्क देखने को मिलेगा। आपके बाल भी ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी नजर आएंगे।

इन बातों का रखें ध्यान

इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें हफ्ते में 1 बार ही इसका इस्तेमाल करें हमेशा ताजे फूलों का इस्तेमाल करें

केमिकल डाय के साथ इसे मिक्स न करें। तो अगर आप भी नेचुरल तरीके से बालों को बरगंडी करना चाहती हैं, तो गुड़हल के फूलों वाला ये नुस्खा कमाल का है। अगर आप नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करेंगी तो बालों में फर्क जरूर देखने को मिलेगा।

तुरई के छिलकों से बनाएं कबाब और चटनी

हमारे यहां भारतीय घरों में कई तरह की चीजें बनाई और खाई जाती हैं। ये खाने में इतनी स्वादिष्ट होती हैं कि कोई भी इनका स्वाद भूल नहीं पाता है। यहां हर मौसम के हिसाब से सब्जियां मिलती हैं। सर्दियों में जहां गोभी और मटर की भरमार देखने को मिलती है, तो वहीं गर्मियों में परवल, करेला, भिंडी और लौकी की सब्जी खूब खाई जाती है। तुरई भी उन्हीं में से एक है।

तुरई के छिलकों से क्या बनाया जा सकता है ?

तुरई के छिलकों से कबाब और चटनी तो बनती ही है, साथ ही स्वादिष्ट सब्जी भी बनाती हैं, जो दाल, चावल या रोटी के साथ खाने से बहुत ही अच्छी लगती है। खास बात तो ये है कि इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। ये न केवल खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी अच्छे माने जाते हैं।



तुरई के छिलकों से बनाएं कबाब

तुरई के छिलकों से कबाब बनाने के लिए सबसे पहले छिलकों को अच्छे से धोकर बारीक काट लें। अब इसमें उबले हुए आलू मैश करके मिला दें। थोड़ा बेसन और पसंदीदा मसाले डालकर एक अच्छा सा मिश्रण तैयार कर लें। अब छोटे-छोटे कबाब बनाकर तवे पर हल्का तेल डालकर सेक लें। आप चाहें तो छिलकों को बारीकी से चाँप भी कर सकती हैं। ये

कबाबा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। आप इन्हें चाय के साथ सर्व कर सकती हैं। चाहें तो डिनर में पराठे के साथ भी खा सकती हैं।

तुरई के छिलकों की बनाएं चटनी

आमतौर पर लोग धनिया, पुदीने, आम, इमली और टमाटर की चटनी बनाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप तुरई के छिलकों की चटनी भी बना सकती हैं ? जी हां, इसे बनाने के लिए पहले छिलकों को थोड़ा सा तेल डालकर भून लें। अब इन छिलकों को मिक्सर में डालें। साथ में हरी मिर्च, लहसुन और नमक डालकर पीस लें। चटनी को पीसने के बाद इसमें थोड़ा नींबू का रस मिला दें। ये खाने के साथ अलग स्वाद देता है और तो और रोटी-पराठे के साथ खाकर तो मजा आ जाता है।

तुरई के छिलकों की सब्जी भी आपगी पसंद

तुरई के अलावा आप तुरई के छिलकों की सब्जी भी बना सकती हैं। इसके लिए छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इसके बाद कड़ाही में जरूरत के हिसाब से तेल गर्म करें। अब इसमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें। जब इनका कच्चापन खत्म हो जाए तो टमाटर डालकर पका लें। अब कटे हुए छिलके डालकर मसालों के साथ पकाएं। ये सब्जी फटाफट तैयार हो जाती है। आप इसे दाल-चावल या रोटी के साथ सर्व करें।

जन जन विचार

RNI Regd No. ASMUL/25/A2367

Head Office : Golapi Market, 1st Floor, Beltola, Guwahati 781029
Branch Office : JanJan Vichar, GMCH Road, Harbala Market, Bhangagarh, Guwahati - 781005
Contact : 6900126012
Email: official.janjanvichar@gmail.com
Website: WWW.janjanvichar.in

ग्राहक सदस्यता फॉर्म

ग्राहक विवरण

पूरा नाम :
पूरा पता :
मोबाइल : हवाद्सम्प
ई-मेल (यदि हो) :

सदस्यता विवरण

अवधि : 1 वर्ष सुल्क : ₹. 500/ गान

भुगतान विवरण

यूपीआई बैंक ट्रांसफर

Bank Details
JAN JAN VICHAR
Bank : HDFC, Branch : Guwahati
A/C No. 50200116979015
IFSC : HDFC0000264



इस क्यूआर कोड को स्कैन कर जन जन विचार के बैंक खाते में कितनी राशि भुगतान कर सकते हैं।
(कृपया उपरोक्त में कितनी राशि भुगतान करनी है।)

भुगतान तिथि : रसीद संख्या :

घोषणा

मैं स्वेच्छा से जा जा विचार साप्ताहिक अखबार की एक वर्ष की सदस्यता ग्रहण करता/करती हूँ एवं सभी शर्तों से सहमत हूँ।

ग्राहक के हस्ताक्षर : तिथि :

कार्यालय उपयोग हेतु

सदस्यता क्रमांक : भुगतान प्राप्त रसीद संख्या : प्राप्तकर्ता का नाम :
तिथि : हस्ताक्षर :

रूस से अब और सस्ता तेल नहीं खरीद पाएगा भारत

जन जन विचार
... नई दिल्ली

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पत्रकारों को बताया कि अमेरिका ईरानी और रूसी तेल पर छूट की अवधि नहीं बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि हम रूसी तेल के लिए सामान्य लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करेंगे। न ही ईरानी तेल के लिए सामान्य लाइसेंस का नवीनीकरण करेंगे।

यह बह तेल था जो 11 मार्च से पहले पानी में था। इसलिए इसका पूरा उपयोग हो चुका है। इन कदमों से संकेत मिलता है कि ट्रंप प्रशासन अब प्रतिबंधों में छूट का उपयोग करके तेल की आपूर्ति बढ़ाने और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को कम करने का प्रयास नहीं करेगा।

इन प्रतिबंधों में मिली छूट का भारत को बड़ा फायदा हुआ था क्योंकि इनकी वजह से नई दिल्ली होर्मुज स्ट्रेट के आस-पास पैदा हुई रुकावटों के बावजूद रूसी तेल की खरीद जारी रख सका। इन रुकावटों के कारण समुद्र में कई जहाज फंस गए थे।

रूसी तेल की खरीद पर मिली छूट की वजह से भारत वैश्विक तेल आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित

कर सका। रिपोर्टों के अनुसार, इस अवधि के दौरान भारतीय रिफाइनरों ने लगभग 30 मिलियन बैरल रूसी तेल के ऑर्डर दिए हैं।

रिलायंस समेत प्रमुख रिफाइनरों ने इस साल जनवरी में अमेरिका के दबाव के चलते रोसेनेफ्ट और लुकोइल जैसी रूसी कंपनियों से अपनी खरीद पहले ही कम कर दी थी, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी रणनीति बदल ली और रूसी कंपनियों से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया।

छूट मिलने के बीच ईरान का कच्चा तेल ले जाने वाले कम से कम दो सुपरटैंकर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे। लगभग सात वर्षों में यह इस तरह की पहली खेप है। ऐतिहासिक रूप से भारत ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख खरीदार रहा है। रिफाइनरियों के साथ बेहतर अनुकूलता और व्यापार की अनुकूल शर्तों के कारण भारत, ईरान के हल्के और भारी ग्रेड के कच्चे तेल की बड़ी मात्रा में आयात करता रहा है।

मार्च में जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले प्रमुख ऊर्जा मार्ग को अपनी पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था, तब अमेरिका ने 30 दिनों का एक लाइसेंस जारी किया था।

व्हाइट हाउस ने ठुकराई संघर्ष-विराम बढ़ाने की मांग

जन जन विचार
... नई दिल्ली

अमेरिकी व्हाइट हाउस ने बुधवार को साफ किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के साथ चल रहे सीजफायर को बढ़ाने की कोई औपचारिक मांग अभी नहीं की है। हालांकि दोनों देशों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करोलाइन लेविट ने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा, आज सुबह कुछ मीडिया में यह खबर आई कि हमने सीजफायर बढ़ाने की औपचारिक मांग की है। यह फिलहाल सही नहीं है।

उन्होंने प्रेस ब्रिफिंग में आगे कहा, हम इन वार्ताओं और बातचीत में पूरी तरह सक्रिय हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ने इस सप्ताह जो कहा, उससे साफ है कि ये बातचीत श्रद्धांजलि और जारी हैं। हम यहीं पर हैं। लेविट ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन सौदे की संभावनाओं को लेकर सतर्क आशावादी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल दिए गए एक इंटरव्यू में भी इसकी बात कही थी। ईरान को वाशिंगटन की स्थिति स्पष्ट रूप से बता दी गई है।

पाकिस्तान में हो सकती है नई चर्चाएं

प्रेस सचिव ने जोर देकर कहा, ईरान के हित में है कि वह राष्ट्रपति की मांगों को मानें। ट्रंप ने इन वार्ताओं में अपनी रेड लाइन्स बहुत साफ कर दी हैं। आगामी वार्ता के स्थान के बारे में पूछे जाने पर लेविट ने कहा कि चर्चाएं बहुत संभावना हैं कि पिछले दौर की तरह ही जगह पर होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ही इस दुद्रव्यस्थिति में एकमात्र मध्यस्थ है, जबकि दुनिया के कई देश मदद की पेशकश कर रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि वाशिंगटन ईरान से जुड़े वित्तीय लेन-देन पर नजर रखे हुए है। उन्होंने चीनी बैंकों को चेतावनी दी कि अगर ईरानी पैसे उनके अकाउंट्स से गुजरते पाए गए तो सैंकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं।

बेसेंट ने कहा कि ईरान पहले दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद प्रायोजक देश था। चीन ईरानी तेल का 90% से ज्यादा खरीद रहा था। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज में ब्लॉकेड के कारण चीन की

खरीदारी में रुकावट आएगी।

पाकिस्तान की मध्यस्थता प्रयास

इस बीच पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। वे इंडोरियर मंत्री मोहसिन नकवी के साथ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात कर रहे हैं। यह दौरा इस्लामाबाद टॉक्सिक विफल होने के बाद दूसरे दौर की वार्ता को पुनर्जीवित करने का अंतिम प्रयास माना जा रहा है।

ईरानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का आभार जताया और कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को दर्शाती है।

यह घटनाक्रम दो सप्ताह के नाजुक सीजफायर के बीच हो रहा है। 11-12 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी अधिकारियों के बीच 21 घंटे तक चली सीधी बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हुई थी। मुख्य विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर था।

राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा था कि सीजफायर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ सकती, लेकिन बातचीत से सुलझाया जाना बेहतर विकल्प है।

खाड़ी में संकट का भारत पर पड़ेगा असर

मुख्य आर्थिक सलाहकार की चेतावनी- 10 अरब डॉलर तक का नुकसान संभव

जन जन विचार
... वाशिंगटन

खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक व्यवधान जारी रहने की स्थिति में भारत में आने वाले धन (रेमिटेंस) पर दबाव पड़ सकता है। इससे 10 अरब डॉलर तक का संभावित नुकसान हो सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने यह बात कही।

अनंत नागेश्वरन 'अमेरिका-भारत आर्थिक मंच-2026' को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रमुख मेजबान देशों में भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक मंदी के कारण विदेश से आने वाले पैसे की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला। भारत को 2024-25 में लगभग 124 अरब डॉलर की रेमिटेंस प्राप्त हुई। इससे यह भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में से एक बन गया। इसमें से लगभग

आधा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय कामगारों से आया।

उन्होंने कहा, सामान्य आर्थिक गतिविधियों को बहाल होने में जितना समय लगेगा, खाड़ी देशों में काम करने वाले श्रमिकों की ओर से भेजे जाने वाले धन पर इसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि व्यवधान की अवधि और गंभीरता के आधार पर संभावित असर पांच अरब डॉलर से 10 अरब डॉलर तक हो सकता है। नागेश्वरन ने कहा कि ये जोखिम कई कारकों से पैदा होते हैं, जिनमें संघर्ष के कारण श्रमिकों की वापसी, मेजबान देशों में धीमी आर्थिक गतिविधि और रोजगार की स्थिति के बारे में अनिश्चितता शामिल है।

खाड़ी क्षेत्र भारतीय प्रवासी कामगारों के लिए बड़ा केंद्र है। यहां निर्माण, सेवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं।

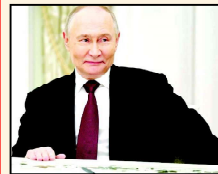
अगर परेशानी लंबी चली, तो उनकी कमाई घट सकती है और काम पर लौटने में देरी हो सकती है।

यह चिंता ऐसे समय आई है, जब दुनिया में पहले से अनिश्चितता है। व्यापार, ऊर्जा बाजार और पूंजी प्रवाह पर असर पड़ रहा है। नागेश्वरन ने कहा कि रेमिटेंस उन चार बड़े माध्यमों में से एक है, जिनसे बाहरी झटके भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी भारत की स्थिति मजबूत है। विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा है और आय के स्रोत भी अलग-अलग हैं।

उन्होंने कहा, हम इस स्थिति में मजबूत आर्थिक आधार के साथ प्रवेश कर रहे हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है। लाखों भारतीय विदेश में काम करते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के देश इस आबादी का बड़ा हिस्सा रखते हैं। इसलिए यह क्षेत्र भारत के लिए बहुत अहम है।

भारत आएंगे पुतिन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग

जन जन विचार
... मास्को



रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक वार्षिक बैठक है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के नेता शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें नए सदस्य देश भी शामिल हैं।

इस बैठक में आर्थिक सहयोग, व्यापार, वैश्विक शासन और भू-

राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। यह मंच उभरती अर्थव्यवस्थाओं को नीतियों के समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सामूहिक आवाज उठाने का अवसर देता है।

रूसी समाचार एजेंसी तास ने क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के हवाले से जानकारी दी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस साल भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में निश्चित रूप से शामिल होंगे।

अभी तक शिखर सम्मेलन की आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन पहले 'तास' ने भारत सरकार के एक सूत्र के हवाले से बताया था कि यह सम्मेलन 12 से 13 सितंबर के बीच आयोजित किया जा सकता है।

सीबीएसई 10वीं में 93.70 फीसदी परीक्षार्थी पास

जन जन विचार
... नई दिल्ली

सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए हैं। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार कुल 93.70 प्रतिशत छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। परिणामों के अनुसार 92.69 प्रतिशत लड़कों ने परीक्षा पास की, जबकि 94.99 प्रतिशत लड़कियां सफल रहीं, जिससे एक बार फिर छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए लड़कों को पीछे छोड़ दिया है।

सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा के परिणाम घोषित होने पर, सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, 'यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिश के अनुसार, दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गईं और आज एक महीने के भीतर हमने भारत के स्कूलों के साथ-साथ 26 देशों में हमारे संबद्ध स्कूलों के कक्षा 10 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। 24,83,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, उत्तीर्ण प्रतिशत 93.70 है, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बेहतर है... हर

साल की तरह, लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है...।

इस बार सीबीएसई ने परीक्षा प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव किया है। एलओसी से जुड़ी पूरी जिम्मेदारी अब स्कूलों को दी गई है। स्कूल के प्रिंसिपल और संबंधित स्टाफ को निम्न काम करने होंगे- यह सुनिश्चित करना कि कौन से छात्र दूसरी परीक्षा देने के योग्य हैं, सुधार या कंपार्टमेंट वाले छात्रों के विषयों की सही जानकारी दर्ज करना, छात्रों के सभी डाटा की जांच करना, तय समय सीमा के भीतर सीबीएसई पोर्टल पर जानकारी अपलोड और फाइनल करना।

दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए एलओसी जमा करने की प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू होगी। यह प्रक्रिया केवल 5 दिनों के लिए खुली रहेगी, यानी स्कूलों को बहुत कम समय में सभी जरूरी काम पूरे करने होंगे। जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए सीबीएसई ने सेशन-2 परीक्षा का विकल्प दिया है। यह परीक्षा 15 मई से 1 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। इस दौरान छात्र अधिकतम 3 विषयों में अपने अंक सुधार सकते हैं।

गुवाहाटी के अनन्यम लॉय बरुवा को मिले 99 फीसदी अंक



जन जन विचार
... गुवाहाटी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं कक्षा के घोषित परिणामों में गुवाहाटी के छात्र अनन्यम लॉय बरुवा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पांच रैंक धारकों में अपनी जगह बनाई है।

गुवाहाटी फिसड्डी

गुवाहाटी : सीबीएसई के 10वीं के नतीजों में इस बार जहां देशभर में कुल पास प्रतिशत 93.70 प्रतिशत रहा, वहीं गुवाहाटी क्षेत्र केवल 85.32 प्रतिशत के साथ सबसे नीचे रहा। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के भीतर छिपी असमानताओं की कहानी भी कहता है।

जब देश के कई क्षेत्र 95 प्रतिशत से ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब गुवाहाटी का 85.32 प्रतिशत परिणाम कुछ बड़े सबाल खड़े करता है।

गुवाहाटी और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में अब भी अच्छे स्कूल और शिक्षकों की कमी है। डिजिटल सुविधाओं की सीमित पहुंच है, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां तो हैं ही, साथ ही यहां प्रतियोगी माहौल का सर्वथा अभाव है। ये सभी कारण छात्रों के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।

सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल के 9175 पदों पर भर्ती

जन जन विचार
... नई दिल्ली

नई दिल्ली। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की ओर से कॉन्स्टेबल (टेबिनकल/ट्रेड्समैन/पायनियर-मेल/फीमेल) के बंपर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 19 मई 2026 तक जारी रहेगी।

जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।

पात्रता एवं मापदंड : इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से मैट्रिकुलेशन (10वी) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही पद के अनुसार उम्मीदवार

के पास संबंधित ट्रेड में अनुभव/आईटीआई सर्टिफिकेट/ हैवी ट्रांसपोर्ट वैहिकल ड्राइविंग लाइसेंस आदि होना चाहिए। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार की आयु कॉन्स्टेबल ड्राइवर पद के लिए 21 से 27 वर्ष और अन्य सभी पदों के लिए 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को उम्र में नियमानुसार छूट मिलेगी।

इस भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को फीस के रूप में 100 रुपए जमा करना होगा। एससी, एसटी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए निशुल्क फॉर्म भर सकेंगे।

इस भर्ती में चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट/स्क्रिल टेस्ट/पीईटी, पीएसटी/डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन/मेट्रिकल एग्जामिनेशन आदि से गुजरना होगा।

सीबीएसई 10वीं में कई को मिले शत प्रतिशत अंक नई दिल्ली।

सीबीएसई 10वीं के 2026 के परिणामों में कई छात्रों ने 100 प्रतिशत अंक हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया। दक्ष वासुदेव ने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ-स्टडी के दम पर 500/500 अंक प्राप्त किए। उन्होंने रोज 12-13 घंटे पढ़ाई कर हर विषय को गहराई से समझा। वहीं तनय श्रीवास्तव ने बिना तय टाइमटेबल के पढ़ाई करते हुए सभी मुख्य विषयों में 100 अंक हासिल किए। देशभर में कई अन्य छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इस बार का परिणाम खास इसलिए रहा क्योंकि अधिकतर टॉपर्स ने कोचिंग के बजाय आत्म-अध्ययन पर भरोसा किया। यह सफलता बताती है कि सही रणनीति, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं और विद्यार्थी अपनी मेहनत से नई मिसाल कायम कर सकते हैं।

सोशल साइंस की पढ़ाई के बाद करियर के ऑप्शन

जन जन विचार
... नई दिल्ली

आज के दौर में करियर विकल्प केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गए हैं। खासकर सोशल साइंस जैसे विषय, जिन्हें अक्सर केवल थ्योरी तक सीमित समझा जाता है, अब युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहे हैं। सिविल सेवा से लेकर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल रिसर्च और ऑर्गनाइजेशनल साइकोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सोशल साइंस के छात्र अपनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं।

सिविल सर्वेंट : सोशल साइंस ग्रेजुएट छात्रों के लिए सबसे कॉमन करियर ऑप्शन है सिविल सेवा। आप किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद सिविल सेवा की परीक्षा में भाग ले कर ब्यूरोक्रेट का हिस्सा बन सकते हैं।

इकोनॉमिस्ट : एक इकोनॉमिस्ट आमतौर पर उत्पादों और सेवाओं की डिमांड और सप्लाई के आंकड़ों की जांच करता है। वे टैक्स रेट, बिजनेस साइकल, इकोनॉमिक

डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में मात्रात्मक और गुणात्मक रिसर्च करते हैं। अगर आप अर्थशास्त्र में गहन ज्ञान और रुचि रखते हैं तो सोशल साइंस ग्रेजुएट्स के लिए यह एक बेहतर करियर विकल्प है।

पॉलिटिकल साइंटिस्ट : जैसा कि नाम से ही पता चलता है पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉलिटिकल ट्रेड, पॉलिसी, आईडिया पॉलिसी को समझने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक रिसर्च की मदद लेता है। अधिकतर, राजनीतिक वैज्ञानिक सरकारी विभागों, थिंक टैंक, शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ गैर-लाभकारी संगठनों के भीतर काम करते हैं।

ऑर्गनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ऑर्गनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट सोशल साइंस ग्रेजुएट के लिए एक उभरता हुआ करियर ऑप्शन है। यह एक ऑर्गनाइजेशन में वर्कप्लेस में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में एक्सपर्ट अक्सर मैनेजमेंट के साथ सहयोग कर कंपनी में स्टाफ की हायरिंग और ट्रेनिंग का कार्य भी करते हैं।

आर वैशाली ने रचा इतिहास

कैंडिडेट्स शतरंज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं



जन जन विचार
... नई दिल्ली

भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने साइप्रस में आयोजित फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतकर यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव प्राप्त किया। इस जीत के साथ वैशाली को अब चीन

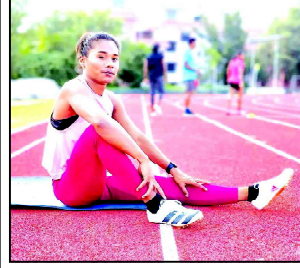
की मौजूदा विश्व चैंपियन जू वेनजुन के खिलाफ महिला विश्व चैंपियनशिप मुकाबला खेलने का मौका मिलेगा। भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अब भारत के पास ओपन और महिला, दोनों विश्व खिताब मुकाबलों में प्रतिनिधित्व होगा। गौरतलब है कि डी गुकेश पहले ही ओपन वर्ल्ड चैंपियन हैं।

आखिरी राउंड में वैशाली को जीत के साथ-साथ अन्य मुकाबलों के नतीजों पर भी निर्भर रहना था। दिव्या देशमुख ने बिबिसारा अस्साउबायेवा को ड्रॉ पर रोककर वैशाली के लिए रास्ता आसान किया। इसके बाद वैशाली ने सफेद मोहरों से खेलते हुए कैटेरीना लाग्नो को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया।

वैशाली ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने तान झोंगयी और अलेक्जेंड्रा गोर्याचिकिना जैसी मजबूत खिलाड़ियों को हराया, जबकि अन्ना मुजीचुक के खिलाफ महत्वपूर्ण ड्रॉ हासिल किया। हालांकि उन्हें झू जिनर के खिलाफ दो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अपने अभियान को पटरी पर बनाए रखा।

अब वैशाली का सामना जू वेनजुन से होगा, जो पांच बार की विश्व चैंपियन हैं। यह मुकाबला इस साल के अंत में खेला जाएगा और इसमें लगभग 2.7 करोड़ रुपए की इनामी राशि दांव पर होगी।

लॉस एंजेलिस 2028 मेरा सपना : हिमा दास



जन जन विचार
... नई दिल्ली

असम की स्टार धाविका हिमा दास ने कहा है कि उनका लक्ष्य 2028 में होने वाले लॉस एंजेलिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना है। उन्होंने बताया कि हर खिलाड़ी की तरह उनका भी सपना ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करना है।

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान हिमा ने भारतीय एथलेटिक्स में हो रहे

बदलावों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अब छोटे शहरों और गांवों के खिलाड़ियों को भी आगे आने का मौका मिल रहा है, जो पहले उतना आसान नहीं था। हिमा दास ने इस बदलाव का श्रेय एथलेटिक्स फेडरेशन

ऑफ इंडिया को दिया। उनके अनुसार, संघ ने सरकार के साथ मिलकर नीचे स्तर से खेल को मजबूत करने के लिए काम किया है, जिससे नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वर्षों में भारत खेलों में और बेहतर करेगा। 2030 में बड़े खेल आयोजन और 2036 में ओलंपिक की संभावित मेजबानी को देखते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय खिलाड़ी तब तक और मजबूत स्थिति में होंगे।

आईपीएल की बस... केवल बस नहीं! चलते-फिरते पांच सितारा होटल

जन जन विचार
... नई दिल्ली

आईपीएल 2026 में अगर आप सोचते हैं कि टीम बस सिर्फ खिलाड़ियों को होटल से स्टेडियम तक ले जाने का जरिया होती है, तो आप गलत हैं। ये बसें असल में चलते-फिरते फाइव स्टार होटल हैं, जिन्हें खास तौर पर खिलाड़ियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। इन बसों में खिलाड़ियों को



पर एक बस पर लगभग 70 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक खर्च करती है। यानी औसतन देखा जाए तो एक बस की कीमत करीब एक करोड़ रुपए के आसपास होती है।

करती हैं, ताकि खिलाड़ियों को यात्रा के दौरान आरामदायक और रिलैक्स माहौल मिल सके। इसमें एडवांस सीटिंग सिस्टम, हाई-टेक एंटरटेनमेंट और स्मूद ट्रेवल के लिए बेहतर सर्विसेशन भी हैं। इन सभी चीजों की वजह से लागत काफी बढ़ जाती है।

आईपीएल में हर चीज ब्रांडिंग से जुड़ी होती है और टीम बस भी इसका अहम हिस्सा है। हर बस को टीम के रंग, स्पॉन्सर लोगो और खिलाड़ियों की तस्वीरों से सजाया जाता है। इससे यह सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं रहती, बल्कि पूरे सीजन के दौरान फ्रेंचाइजी की चलती-फिरती पहचान बन जाती है।

अगर आप आईपीएल टीम बस के अंदर जाएं, तो यह किसी लज्जरी लाउंज से कम नहीं लगेगी। खिलाड़ियों के लिए इसमें चोड़ी और रिक्लाइनिंग सीट्स, एकस्ट्रा लेगरूम, पर्सनल चार्जिंग पोर्ट और कभी-कभी मसाज फंक्शन वाली सीट्स

मिलती हैं। इसके अलावा बस में हाई-स्पीड वाई-फाई, एलईडी स्क्रीन और प्रीमियम साउंड सिस्टम भी लगी होती हैं। कई टीम बसों में मिनी फ्रिज भी होते हैं, जिनमें ड्रिंक्स रखे जाते हैं। साथ ही एम्बिगेंट लाइटिंग और क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम खिलाड़ियों को हर मौसम में आरामदायक माहौल देता है।

इन बसों की कीमत ज्यादा होने का एक बड़ा कारण सुरक्षा भी है। मैच के दिन टीम बसें कड़ी सुरक्षा के बीच चलती हैं और कई बार पुलिस एस्कोर्ट भी साथ होता है। रूट पहले से प्लान किए जाते हैं ताकि ट्रैफिक या देरी

सपोर्ट स्टाफ के लिए। इसके अलावा तीसरी बस भी होती है, जो उपकरणों (इक्विपमेंट) के लिए होती है। इससे टीम का मूवमेंट बेहतर और व्यवस्थित रहता है।

समय के साथ आईपीएल बसें सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं रहीं, बल्कि ड्रेसिंग रूम का एक्सटेंशन बन गई हैं। खिलाड़ी इन बसों में मैच रणनीति पर चर्चा करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं। तेज रफतार वाले आईपीएल सीजन में ये छोटे-छोटे सफर भी टीम बॉन्डिंग के लिए बेहद अहम हो जाते हैं।

आज के दौर में आईपीएल



वही सुविधाएं मिलती हैं, जो किसी लज्जरी लाउंज या प्राइवेट स्पेस में मिलती हैं।

आईपीएल टीम बस की कीमत साधारण बसों से कई गुना ज्यादा होती है। एक फ्रेंचाइजी अपनी जरूरत, कस्टमाइजेशन, ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी के आधार

जितना ज्यादा लज्जरी और हाई-टेक फीचर्स, उतनी ही ज्यादा इसकी कीमत बढ़ती जाती है।

ये बसें आम कमर्शियल कोच जैसी नहीं होतीं। इन्हें पूरी तरह से मॉडिफाई किया जाता है। टीम प्रीमियम बस मैनुफैक्चरर्स के साथ मिलकर इनका इंटीरियर डिजाइन



की समस्या न हो और टीम समय पर स्टेडियम पहुंचे।

अक्सर फ्रेंचाइजी एक से ज्यादा बसों का इस्तेमाल करती हैं। एक बस खिलाड़ियों के लिए और दूसरी

फ्रेंचाइजी की वैल्यू और फैन एंगेजमेंट लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ये लज्जरी बसें सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि टीम की पहचान, ब्रांड वैल्यू और परफॉर्मंस का भी हिस्सा बन चुकी हैं।

आशा ताई को नम आंखों से विदाई

जन जन विचार
... मुंबई

भारतीय संगीत जगत की अमर आवाज आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहें। 92 वर्ष की आयु में उनके निधन के बाद पूरे देश ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। मुंबई के शिवाजी पार्क श्मशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके बेटे आनंद भोसले ने मुखार्पण दी।

आशा भोसले को सीने में संक्रमण और अत्यधिक थकान के कारण मुंबई के ब्रीच केंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान कई अंगों के फेल हो जाने से उनका निधन हो गया।

इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके लोअर परेल स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां हजारों प्रशंसकों और कई नामचीन हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

जब आशा भोसले की अंतिम यात्रा उनके घर से शिवाजी पार्क की ओर निकली, तो रास्तों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोग घरों की छतों और खिड़कियों से 'आशा ताई' को अंतिम विदाई दे रहे थे।

उनके पार्थिव शरीर को फूलों से सजे वाहन में ले जाया गया, जिसमें उनकी मुस्कुराती तस्वीर ने हर किसी को भावुक कर दिया।

शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान फिल्म और संगीत जगत की कई



बड़ी हस्तियां और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।

अंतिम दर्शन के दौरान पृष्ठभूमि में उनके सदाबहार गीत 'आओ हजूर तुमको', 'आइए मेहरबान', 'झुमका गिरा रे', 'दिल चीज क्या है', 'ओ साथी रे' धीमे-धीमे बजते रहे। यह पल हर किसी को यह एहसास करा रहा था कि आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनके सुर हमेशा जीवित रहेंगे।

उसी शिवाजी पार्क में उनकी बहन लता मंगेशकर का भी 2022 में अंतिम संस्कार हुआ था। दोनों बहनों ने भारतीय संगीत को जो ऊंचाई दी, वह इतिहास में सदैव अमर रहेगी।

आशा भोसले के जाने से भारतीय संगीत का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है। उनकी आवाज, उनके गीत और उनकी शैली आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

अखबार और फॉयल में खाना रखना खतरनाक

जन जन विचार
... नई दिल्ली

घर हो या बाजार-रोटी, समोसा, कचौरी या टिफिन अक्सर खाने की चीजें अखबार या एल्युमिनियम फॉयल में लपेटकर रखी जाती हैं। यह आदत सालों से चली आ रही है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है-क्या यह आदत आपकी सेहत के लिए खतरनाक है? क्या इससे कैंसर तक हो सकता है?

अखबार की स्याही में कई तरह के हानिकारक केमिकल और रंग मौजूद होते हैं। जब गर्म या तेलयुक्त खाना इसमें रखा जाता है, तो ये केमिकल आसानी से खाने में मिल सकते हैं और सीधे शरीर में पहुंच जाते हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से शरीर में विषाक्त तत्व बढ़ सकते हैं, पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, संक्रमण (इन्फेक्शन) का खतरा बढ़ता है।

एल्युमिनियम फॉयल : पूरी तरह सुरक्षित नहीं। अखबार के मुकाबले एल्युमिनियम फॉयल थोड़ा बेहतर जरूर है, लेकिन यह भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। खासतौर पर जब आप इसमें बहुत गरम खाना, खट्टा या मसालेदार भोजन रखते हैं, तो फॉयल से थोड़ा एल्युमिनियम खाने में मिल सकता है।



हालांकि यह मात्रा कम होती है, लेकिन बार-बार इस्तेमाल करने से शरीर पर इसका असर पड़ सकता है।

क्या इससे कैंसर होता है? यहां सच जानना जरूरी है-कभी-कभी अखबार या फॉयल में खाना रखने से कैंसर का सीधा प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन, लगातार और लंबे

समय तक ऐसा करने से शरीर में हानिकारक तत्व जमा हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

गलत आदतें जो नुकसान बढ़ाती हैं। रोटी की टोकरी में अखबार बिछाना, गर्म खाना सीधे फॉयल में कसकर लपेटना, फॉयल में रखे खाने को दोबारा गर्म करना।

ये आदतें केमिकल के रिसाव को और बढ़ा देती हैं। सुरक्षित विकल्प क्या हैं? अगर आप सच में अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, तो ये बेहतर विकल्प अपनाएं-

स्टील के बर्तन, कांच के कंटेनर, केले के पत्ते, साफ सूती कपड़ा, फूड-ग्रेड या बटर पेपर।

चुटकुले

पत्नी (गुस्से में)- अरे देख लेना तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी

पति- अरे ठीक है, वैसे भी मैं हर जगह तेरे साथ आना भी नहीं चाहता हूँ।

बीवी- सुनो जी, जब हमारी नई-नई शादी हुई थी... जब मैं खाना बना कर लाती थी तो तुम खुद कम खाते थे, मुझे ज्यादा खिलाते थे।

पति- तो ?

बीवी- तो अब ऐसा क्यों नहीं करते हो ?

पति- क्योंकि अब तुम अच्छा खाना बनाना सीख गई हो।

'यूपी वाली, बिहार वाली' का फर्स्ट लुक जारी

जन जन विचार
... मुंबई

भोजपुरी सिनेमा की दो चर्चित अभिनेत्रियां रानी चटर्जी और संजना पांडेय अपनी अपकमिंग फिल्म 'यूपी वाली, बिहार वाली' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प सवाल टैंड करने लगा है-आखिर इनमें से यूपी वाली कौन है और बिहार वाली कौन ?

पोस्टर में दोनों अभिनेत्रियां साड़ी में नजर आ रही हैं, लेकिन अंदाज बिल्कुल अलग है। संजना पांडेय जहां सिर पर पल्लू ओढ़े पारंपरिक लुक में दिखाई देती हैं, वहीं रानी चटर्जी बिना पल्लू के



साड़ी में अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आती हैं। यही कॉन्ट्रास्ट अब दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

मेकर्स ने पोस्टर के साथ सिर्फ फिल्म का नाम साझा किया, लेकिन यह नहीं बताया कि कौन किस

राज्य का किरदार निभा रही है। इसी सस्पेंस ने दर्शकों को उत्सुकता और बढ़ा दी है।

इस फिल्म की खास बात यह भी है कि रानी चटर्जी और संजना पांडेय पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं। भोजपुरी

इंडस्ट्री में रानी चटर्जी अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और बॉल्ड किरदारों के लिए जानी जाती हैं, जबकि संजना पांडेय ने भी कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली है।

फिल्म का निर्देशन मंजुल ठाकुर कर रहे हैं, जबकि कहानी अरविंद तिवारी ने लिखी है।

फिल्म में दोनों अभिनेत्रियों के बीच नोकझोंक, तकरार और हलकी-फुल्की कॉमेडी देखने को मिलेगी, जो दर्शकों को बांधे रखेगी। पोस्टर से ही यह साफ है कि फिल्म दो अलग-अलग संस्कृतियों के टकराव और तालमेल की कहानी हो सकती है, जिसमें मनोरंजन का पूरा तड़का होगा।